ALL INDIA FORUM AGAINST PRIVATISATION (AIFAP)

AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL!

Website: https://aipaf.org.in
Email: contact@aifap.org.in
WhatsApp Number: +918454018757

प्रेस वक्तव्य

4 अप्रैल 2022

LIC IPO निकालने के सरकार के फैसले की निंदा करें

बीमा क्षेत्र के श्रमिकों और LIC के बड़ी संख्या में पॉलिसीधारकों के कड़े विरोध के बावजूद LIC के IPO के साथ आगे बढ़ने के केंद्र सरकार के फैसले की सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) कड़ी निंदा करता है। इसने बड़े भारतीय और विदेशी वित्तीय निवेशकों और संस्थानों को लाभान्वित करने के लिए श्रमिकों और लोगों की सभी आशंकाओं और दलीलों की अनदेखी की है।

सरकार का यह दावा झूठा है कि LIC के 3.5% शेयरों का विनिवेश निजीकरण नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि यह विनिवेश LIC के निजीकरण की शुरुआत है। SEBI लिस्टिंग मानदंडों के अनुसार, सरकार को अगले कुछ वर्षों में LIC के कम से कम 25% शेयरों का विनिवेश करना होगा। इसके अलावा, यह पता चला है कि सीमा को 25% से बढ़ाकर 35% करने पर SEBI विचार कर रहा है।

यह सर्वविदित है कि LIC के शेयर सूचीबद्ध हो जाने के बाद LIC का पूरा उद्देश्य पॉलिसीधारकों को लाभ को अधिकतम करने के बजाय शेयरधारकों के मुनाफ़े को अधिकतम करने में बदल जाएगा। निवेशकों के लिए IPO को आकर्षक बनाने के लिए पॉलिसीधारकों के लिए लाभ के हिस्से को 95% से 90% तक कम करके पहला कदम उठाया जा चुका है। यह अपेक्षा है कि शेयरधारक मूल्य में वृद्धि के लिए आने वाले वर्षों में पॉलिसीधारकों की हिस्सेदारी में और कमी की जाएगी। LIC के अध्यक्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि IPO के बाद शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए कई अन्य कदमों की योजना बनाई गई है। लाभ को अधिकतम करने के लिए LIC जोखिम भरे निवेश का सहारा ले सकती है। IPO के परिणामस्वरूप LIC के 40 करोड़ से अधिक पॉलिसीधारकों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।

LIC की 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति लाखों श्रमिकों और एजेंटों की मेहनत और 65 वर्षों में पॉलिसीधारकों के दसियों करोड़ रुपयों से बनाई गई है। राष्ट्रीयकरण के समय LIC में सरकार ने केवल रु. 5 करोड़ की पूंजी लगाई थी। कुछ साल पहले ही LIC में सरकार के निवेश को रु. 100 करोड़ तक बढ़ाया गया था। LIC वास्तव में उसके पॉलिसीधारकों का ही है। LIC IPO अपने वास्तविक मालिकों के हितों की अनदेखी करता है।

IPO के बाद LIC का फोकस लागत कम करने पर रहेगा ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके। इससे दूरदराज के क्षेत्रों और छोटे पॉलिसीधारकों को बीमा से वंचित होना पड़ेगा क्योंकि वे बहुत लाभदायक नहीं हैं। LIC ने देश में और छोटे पॉलिसी धारकों के बीच व्यापक रूप से बीमा फैलाया था जिसके कारण इसका औसत प्रीमियम रु. 11,000 है जब कि उसकी तुलना में निजी बीमा कंपनियों का औसत प्रीमियम रु. 76,000 है, क्योंकि वे बड़े पॉलिसी धारकों और शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निजीकरण के कारण कर्मचारियों का काम का बोझ बढ़ेगा और उनकी संख्या कम होगी।

IPO को तेजी से जारी करके और LIC के मूल्यांकन में भारी कमी करके, LIC से बीमा प्राप्त करने वाले करोड़ों लोगों की कीमत पर, बड़े भारतीय और वित्तीय सट्टेबाजों की मदद करने के लिए सरकार ने बहुत फुर्ती दिखाई है। इन सट्टेबाजों ने पहले सरकार से कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण IPO को मार्च से बाद की तारीख तक के लिए टाल दिया जाए। इसके बाद उन्होंने सरकार से LIC के मूल्यांकन को 16 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 6 लाख करोड़ रुपये करने को कहा।

सिर्फ दो महीने में LIC का मूल्य घटकर आधे से भी कम कैसे हो सकता है? सरकार कम मूल्यांकन के लिए सहमत हो गयी, जिससे IPO के लिए शेयर मूल्य काफी कम किया गया। तब सरकार को IPO जल्दी करने की सलाह दी गई, हालाँकि युद्ध अभी भी जारी है! शेयर की कीमत में कमी के कारण सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपये से वंचित हो रही है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि बाद में LIC शेयर की कीमत अपने वास्तविक मूल्य तक बढ़ने पर वित्तीय सट्टेबाजों को भारी लाभ मिल सके। सट्टेबाजों के पक्ष में मूल्यांकन को इस तरह कम करने से सरकार को जो नुकसान हो रहा है, वह LIC के पॉलिसीधारकों और भारत के लोगों पर एक और हमला है।

LIC IPO निस्संदेह बड़े निजी भारतीय और विदेशी वित्तीय संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक जनविरोधी, मजदूर विरोधी कदम है।

हम सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम के सदस्य, LIC और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के जनविरोधी निजीकरण की निंदा करते हैं। हम सभी क्षेत्रों और संबद्धताओं से परे अपनी एकता को मजबूत करने और निजीकरण की जन-विरोधी, समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीति को हराने के लिए उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डॉ. ए मैथ्यू

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम के लिए

वर्णमाला क्रम में घटक:

1) एयर इंडिया एम्प्लोयीज यूनियन (AIEU),
2) एयर इंडिया सर्विस इंजिनियर्स एसिओसेशन (AISEA),
3) ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसिओसेशन (AIBOA),
4) ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (AICWF),
5) ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी ऑर्गेनाजेशंस (ऑल इंडिया परिसंघ),
6) ऑल इंडिया डिफेन्स एम्पलोयीज फेडरेशन (AIDEF),
7) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पलोयीज (AIFEE),
8) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (AIFOPDE),
9) ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (AIGC),
10) ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA),
11) ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) एम्प्लोयीज फेडरेशन,
12) ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लोयीज एसोसिएशन - उत्तर रेलवे,
13) ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (AIPMA),
14) ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (AIPDWF),
15) ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF),
16) ऑल इंडिया रेलवे एम्पलोयीज कॉन्फेडरेशन (AIREC) - पश्चिमी क्षेत्र,
17) ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मैंटेनर्स यूनियन (AIRTU),
18) ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF),
19) ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राईब एम्प्लोयीज एसिओसेशन (AISCSTREA),
20) ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एमप्लोयीज फेडरेशन (AISGEF),

21) ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (AISMA),
22) ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन (AITCA),
23) आंध्र प्रदेश स्टेट पॉवर एम्प्लोयीज जॉइंट एक्शन कमिटी (APSPEJAC),
24) बहुजन समाजवादी मंच (BSM),
25) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) एम्पलोयीज एसिओसेशन, पलक्कड़, केरल
26) भारत पेट्रोलियम टेक्नीकल और नौन- टेक्नीकल एम्पलोयीज एसोसिएशन (BPTNTEA) - मुंबई रिफाइनरी,
27) भारतीय रेलवे मज़दूर यूनियन (BRMU) एसडव्लू रेलवे, हुबली,
28) बिहार, फुले, अम्बेडकर युवा मंच
29) बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) एम्प्लोयीज यूनियन,
30) बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) कामगार संघटना,
31) सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (CRMS),
32) चित्तरंजन लोको वर्क्स (CLW) रेलवेमेन्स यूनियन, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
33) चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (CRMC), चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
34) कोचीन रिफाइनरी एम्पलोयीज एसोसिएशन (CREA-INTUC),
35) कोचीन रिफायनरीज वर्कर्स एसोसिएशन (CRWA)-CITU,
36) कन्टेनर कॉर्पोरेशन (CONCOR) एम्पलोयीज यूनियन,
37) कोयला मजदूर यूनियन (एटक)
38) दक्षिण रेलवे एम्पलोयीज यूनियन (DREU),
39) डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स (DMW) रेलवेमेन्स यूनियन, पटियाला, पंजाब,
40) डीजल लोको वर्क्स (DLW) मेन्स यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
41) डीएमडव्ल्यू रेलवे वर्कर्स यूनियन (DMWRWU), पटियाला, पंजाब,
42) इलेक्ट्रीसिटी एम्पलोयीज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI),
43) हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (इंटक)
44) हिंद खदान मजदूर फेडरेशन (HKMF),
45) हिंद मज़दूर सभा (HMS) - तेलंगाना,
46) हिंदुस्तान पेट्रोलियम एम्पलोयीज यूनियन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी,
47) इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (INWEF),
48) इंडियन रेलवे केटरिंग, टूरिज्म, ई-टिकटिंग स्टाफ फेडरेशन (NFIR),

49) इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन (IRLRO),
50) इंडियन रेलवे टिकटचेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (IRTCSO),
51) इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ (ICFMS), चेन्नई, तमिलनाडु,
52) इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु,
53) जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लोयीज एंड इंजीनियर्स कॉर्डिनेशन कमिटी (JKPEECC),
54) जॉइंट एक्शन फ्रंट ऑफ़ पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियनस ऑफ़ बैंगलोर,
55) कामगार एकता कमिटी (KEC)/मजदूर एकता कमिटी (MEC)/तोयिलाली ओट्टूमइ इयक्कम (TOI),
56) लोक राज संगठन (LRS),
57) मध्य प्रदेश यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ पॉवर एम्प्लोयीज इंजीनियर्स,
58) महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (MSBEF),
59) महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऑपरेटर्स संघटना,
60) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (AITUC),
61) मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (MCDLW) वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
62) मुंबई एवं उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ,
63) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट फ्लोटिला वर्कर्स असोसिएशन,
64) नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR),
65) नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एम्पलोयीज (NFTE)-BSNL,
66) नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS),
67) नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (NRMU), मध्य रेलवे/कोंकण रेलवे,
68) नीलाचल एक्जिक्यूटिव्ज एसोसिएशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL),
69) पोर्ट, डॉक एंड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन (AITUC),
70) पुरोगामी महिला संगठन (PMS),
71) रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, कपूरथला, पंजाब,
72) रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
73) रेल कोच फैक्ट्री मजदूर यूनियन (RCFMU), कपूरथला, पंजाब,
74) रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (RCFMC), रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
75) रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) मजदूर यूनियन, बैंगलोर, कर्नाटक,
76) रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (RWFKS), बैंगलोर, कर्नाटक,
77) रिसर्च डिजाइन और स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (RDSO) कर्मचारी संघ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,

78) संचार निगम एक्जिक्यूटिव्ज एसोसिएशन (SNEA)-BSNL,
79) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ऑफिसर्स एसोसिएशन,
80) सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन (AITUC),
81) सिंगारेनी माइनर्स एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन (HMS) - तेलंगाना,
82) साऊथ सेंट्रल रेलवे केटरिंग, हेल्पर्स एवं वर्कर्स यूनियन
83) सदर्न रेलवे एमप्लोयीज संघ (SRES),
84) सबोर्डिनेट इंजीनियर्स एसिओसेशन (एम्एसईबी), SEA)
85) सूरत ट्रेड यूनियन कौंसिल (STUC),
86) तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसिओसेशन (TNEBEA)
87) टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट मुंबई (TDF),
88) यूनियन टेरीटरी (यूटी) पॉवरमेन्स यूनियन, चंडीगढ़,
89) अनऔर्गेनाईज्द वर्कर्स एंड एमप्लोयीज कॉग्रेस,
90) उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन (URMU),
91) वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (CITU),
92) वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लोयीज यूनियन (WCREU),
93) वैस्टर्न रेलवे मजदूर संघ (WRMS).